an>

tilte: Need to enchance the honorarium of Accredited Social Health Activists.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) ः भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत महिलाओं हेतु मातृत्व लाभ की योजना आशा बहुओं के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू है, जिसके परिणामस्वरूप मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है। पूरे देश में लगभग आठ लाख आशा बहुएं जच्चा एवं बच्चा की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को आशा बहुओं द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल ले जाकर प्रसव से पूर्व कम-से-कम तीन बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराने का कार्य किया जाता है। उसके उपरान्त सुरक्षित प्रसव कराने के लिए अस्पताल ले जाती हैं। आशा बहुओं द्वारा जननी शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को जिम्मेदारी से निभाने के बावजूद मात्र 600 रूपए प्रति केस अनुमन्य है। वह भी उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से आशा बहुओं को प्रोत्साहन राशि मिलने में कठिनाई हो रही है, जिसके कारण उनके समक्ष काफी गम्भीर संकट पैदा हो गया है। जबकि आशा बहुओं के द्वारा लगातार प्रोत्साहन राशि की जगह पर 3000 रूपए प्रति माह मानदेय की मांग को लेकर संघर्ष कर रही हैं। इनकी समस्याओं के निदान के लिए इन लोगों ने कई बार जन्तर-मन्तर पर धरना प्रदर्शन भी किया। अतः भारत सरकार से इस मामले पर तुरंत कार्यवाही हेतु अनुरोध है।